

In this situation, setting up of two Mills in Coimbatore would result in stoppage of supply of sugar cane to Chittur Mill from Coimbatore. Therefore, I request the Central Government to take a decision which would ensure regular supply of Sugar Cane to Chittur Sugar Ltd.

(vi) Central Government help to Utter Pradesh in view of power crisis due to fire at Obra Thermal Power Station.

श्री बी०डी०सिंह (फूलपुर) : उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित रूप से भारी विद्युत कटौती के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। यह कटौती गत 13 नवम्बर से लागू की गई। राज्य विद्युत परिषद् की अक्षमता एवं उसमें व्याप्त अनियमितताओं के कारण प्रदेश पहले से ही विद्युत संबंधी समस्याओं के दौर से गुजर रहा था, हाल में ओबरा ताप विद्युत गृह में हुए भयंकर अग्नि कांड ने समस्या को बेकाबू कर दिया है। हर प्रकार के उद्योगों में सप्ताह में तीन दिन विद्युत आपूर्ति बन्द रहेगी। इससे औद्योगिक उत्पादन एवं श्रमिकों की रोजी-रोटी पर छाये संकट का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार कृषि एवं घरेलू उपभोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस समय रबी की बुवाई के लिए खेतों में पानी की आवश्यकता है। परन्तु विद्युत कटौती ने इस क्षेत्र में विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है।

केन्द्रीय ऊर्जा सचिव गत 12 नवम्बर को लखनऊ गये थे और विभिन्न प्रान्तीय अधिकारों से विचार-विमर्श किया है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि प्रांत को सिंगरीली ताप विद्युत इकाई से संभावनानुसार अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति की जाय। अभी तक संभवतः मात्र 16 मेगावाट बिजली यहां से प्रदेश को मिसली

है। प्रदेशीय सरकार ओबरा ताप विद्युत गृह के पुनर्निमाण के लिए केन्द्र से सम्भवतः 30 करोड़ की आर्थिक सहायता भी मांगी है। यदि इन सहयोगों को केन्द्र द्वारा उपलब्ध न कराया गया तो प्रदेश में अभूतपूर्व विद्युत संकट उत्पन्न हो सकता है।

अतएव मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रुचि लेकर उत्तर प्रदेश को वर्तमान विद्युत संकट से आवश्यक सहायता उपलब्ध करा कर उबारने का कष्ट करें।

(vii) Need to supply sufficient quantity of rice to Kerala

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram) : A very serious situation has developed in the State of Kerala due to failure of the centre to supply foodgrains in order to maintain the statutory rationing system in the state. Due to last year's serious drought, the local production of paddy was next to nil; and therefore the availability of rice in the open market is very little; and moreover, due to the restrictions imposed by the surplus states in the matter of buying of Rice from these states by Kerala Civil Supplies Corporation, this is also restricting the rice supply in the state. Consequently, the rationing system in the state is collapsing and the price of Rice is going up daily.

Therefore, it is very urgent that Government of India should supply at least two lakh tonnes of Rice to Kerala state per month to meet the present crisis and to maintain the statutory Rationing system in the state.

(viii) Early completion of Buxer Coiler Dam in Bhojpur

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, भोजपुर जिला अन्तर्गत बक्सर-कोइलवर तटबंध के निर्माण का कार्य विगत 15 वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था।

इसे 1975 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। विगत दो वर्षों से यह घोषणा की जाती है कि इनके तीन सेक्टरों में से सेक्टर ए का काम पूरा हो जायेगा और इसमें बाढ़ का पानी नहीं आएगा। लेकिन इस वर्ष भी बाढ़ का पानी इस सेक्टर में आया और एक सप्ताह तक राष्ट्रीय पथ पर पानी आ जाने के कारण पटना-आरा तथा पश्चिम के अन्य स्थानों का रास्ता अवरुद्ध हो गया।

प्रारम्भ में इस तटबंध योजना की लागत 26.28 करोड़ की थी। मंहगाई के कारण इसके खर्च तिगुने से अधिक हो गए हैं। सेक्टर “वी” और “सी” में तो आधा काम भी नहीं हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत सभी तीनों सेक्टरों में बोल्टर पिचिंग करना भी सम्मिलित है। बक्सर कोइलवर तटबंध योजना में लगभग 71, 650 हेक्टेयर के क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें राजकीय नलकूपों तथा गंगा में हाई पंपिंग सेट लगाकर इस क्षेत्र को सिंचित करने की भी योजना है। लेकिन ये सारी योजनायें खटाई में पड़ी हुई हैं।

इस वर्ष भी सेक्टर “ए” में हर जगह पानी भरा था और अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी करोड़ों रुपये की क्षति हुई। बाँध की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया है। धन का कोई अभाव नहीं है और एक-दो स्थानों को छोड़कर कहीं जन विरोध भी नहीं है। वल्कि जन विरोध का कारण उन्हें मुआवजा न मिलना है। बाँध और नदी के बीच के गाँव की हालत बड़ी दयनीय है। इन्हें अभी तक बाँध के बाहर बसने के लिए योजना के अनुसार बासगत जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि बक्सर कोइलवर तटबंध को आने वाले वर्ष में युद्ध-स्तर पर पूरा करायें।

MR. CHAIRMAN: We now take up the next item.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। खगरिया में पुलिस द्वारा जो मास रेप हुआ था उसके सम्बन्ध में मैंने 377 के अन्तर्गत दिया था लेकिन यह कहा गया कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। मैं जानना चाहूंगा कि रेप स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल सब्जेक्ट है ?

MR. CHAIRMAN: Have you said enough? I will give you my ruling; This should be put up to the Speaker's consideration and it will be done.

CRIMINAL LAW (AMENDMENT BILL—Contd.)

MR. CHAIRMAN: We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri P. Venkatasubbaiah on 18. November, 1983, namely:

‘That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration’.

Now, Shri Amal Datta.

SHRI AMAL DATTA (Dimond Harbour): Mr. Chairman, Sir, the main thing about this Bill and the welcome being is that it has come at last for consideration and passing by the House.

Sir, a hue and cry was raised by the people and by the Press and it was taken up by Parliament as early as in April, 1980. It is on that basis that demands were made that stringent pro-